एफआरआई में बुधवार को केंद्रीय वन मंत्रालय के महानिदेशक डॉ. एसएस नेगी ने कर्मचारी एसोसिएशन के साथ बैठक की। • हिन्दुस्तान

केंद्र देगा पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाएं

वन मंत्रालय

देहरादून | हमारे संवाददाता

वन मंत्रालय के महानिदेशक ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरआई) के कर्मियों को केंद्रीय वन मंत्रालय से पेंशन और मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि एफआरआई वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के लिए योजना जल्द बनाई जाएगी।

आश्वासन

- एफआरआई में केंद्रीय वन मंत्रालय के महानिदेशक ने सुनीं समस्याएं
- आईसीएफआरआई कर्मचारियों को अब केंद्र से मिलेगी पेंशन

बुधवार को एफआरआई में केंद्रीय वन मंत्रालय के महानिदेशक डॉ. एसएस नेगी ने साइंटिस्ट एसोसिएशन, टेक्निकल स्टाफ एसोसिएशन और मिनिस्ट्रीयल स्टाफ एसोसिएशन की समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि एफआरआई के उच्चीकरण के लिए पहले ही पांच करोड़ दिए जा चुके हैं। जरूरत पड़ी तो इसी माह और बजट जारी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की पेंशन और मेडिकल का खर्च केंद्र सरकार ही उठाएगी, जो अब तक विभाग को अपने ही राजस्व से पूरा करना होता था।

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें अब तक चौथे वेतन आयोग का लाभ नहीं दिया जा सका है। नेगी ने जल्द यह लाभ देने की बात कही। बैठक में एफआरआई की डायरेक्टर डॉ. सविता सिंह समेत कई अधिकारी मौजूद रहे।

Hindustan 04-02-16

कार्मिकों ने महानिदेशक के सामने रखीं समस्याएं

देहरादून (एसएनबी)। भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद (आईसीएफआरई) के साइंटिस्ट एसोसिएशन, तकनीकी कर्मचारी संघ व मिनिस्ट्रियल कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने बुधवार को वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के महानिदेशक डा. एसएस नेगी से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराया। महानिदेशक डा. नेगी पिछले तीन दिन से दून में ही हैं। एसोसिएशन व संघ पदाधिकारियों ने महानिदेशक को अवगत कराया कि आईसीएफआरई की स्थापना स्वायत्त संस्थान के रूप में हुई है। लेकिन अन्य स्वायत्त संस्थानों की तरह आईसीएफआरई के सेवारत व सेवानिवृत्त कर्मियों को लाभांश, पेंशन व चिकित्सा सुविधा नहीं मिल रही है।

■ साइंटिस्ट एसोसिएशन व कर्मचारी संघों ने की डा. एसएस नेगी से मुलाकात

पूर्व में भी कई बार इस मुद्दे को उठाया जा चुका है। लेकिन प्रबंधन द्वारा हर बार बजट की तंगी का हवाला दिया जाता है। महानिदेशक डा. नेगी ने एसोसिएशन प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया कि कार्मिकों की न्यायोचित मांगों का समाधान जल्द किया जायेगा। सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन व चिकित्सा सुविधा का लाभ सीएसआईआर के पैटर्न पर लाने की कोशिश की जायेगी। कहा कि अनुसंधान व विकास के साथ ही एफआरआई परिसर के अनुरक्षण के लिए पांच करोड़ का बजट आवंटित किया।

Rastriya Sahara 04-02-16

Dr S S Negi meets FRI associations

DEHRADUN, FEB 3 (HTNS)

Dr S S Negi, Director General, Forests and Special Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi had a long discussion with the several associations of ICFRE and FRI.

It included Forest Scientists Association, ICFRE/FRI, Dehradun (FoSA), Technical Staff Association (TSA) and Ministerial Staff Association (MSA).

These associations discussed following common agenda with a request to make appropriate interventions for their permanent solution.

These included disbursement of pension for ICFRE employees from Consolidated Funds of India as was agreed upon during creation of ICFRE as an autonomous body of the MoEF-&CC, New Delhi.

Extension of medical facility as per CGHS rather than present make shift arrangement through ICFREPHS as well as introduction of cashless system. Strengthening of infrastructure of ICFRE and FRI, and proper maintenance of FRI Estate.

Matters related to one time grant and its diversified uses as well as discontinuation of Chairs of Excellence. Appropriate availability of funds for forestry research, extension and education.

Reinstating robust and quantitative system Pre-2013 Annual Performance Appraisal Report (APAR) system for scientists, which was developed through discussions and deliberations as per DoPT recommendations and duly approved by the BoG. On each of the agenda, Dr Negi assured the association for their amicable solution within a short time. When, he was reminded that FoSA had requested for disbursement of more funds for R&D as well as maintenance of FRI Estate, he told that already Rs 5 Crore had been disbursed. More funds would be made available during February 2016. He assured that ICFRE will brought out of the present mess due to paucity of funds.

On the matter of pension and medical facility to the retired employees, Dr Negi assured that the pension system would be brought on the pattern of ICAR and CSIR for disbursement of pension from Consolidated Fund of India, and once that is completed, retired employees of ICFRE would automatically be covered under CGHS including that of cashless system of treatment. He assured that infrastructure of FRI and its Estate would be developed to cater the requirement of R&D sector of India so to meet national and international expectations. He assured that the matter of technical staff, which has been pending for a long period from 4th Pay Commission, would soon be solved.

He also assured that robust and quantitative system of annual performance appraisal report (APAR) which was applicable upto 2013 would also be reinstated so that the review of scientists could be done appropriately and scientists with higher outcomes could be encouraged and felicitated appropriately.

Dr Savita, Director, FRI was also present in the meeting and supported demands of the associations for better outputs from FRI and ICFRE.

The Himanchal Times 04-02-16